अनुदान संख्या 74 - कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 74 - MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*18,35,00*	*24,18,00*	*22,64,56*	*-1,53,44*
पूरक	*Supplementary*	*5,83,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*50,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2034,28,00	2280,80,00	2234,77,11	-46,02,89
पूरक	Supplementary	246,52,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,95,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*17,02,00*	*45,52,00*	*36,80,08*	*-8,71,92*
पूरक	*Supplementary*	*28,50,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*7,80,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	258,91,00	258,92,00	215,21,35	-43,70,65
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				41,68,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचत (*₹153.44 लाख*) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए *₹583.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 26 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 6 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of revenue section of the grant, the overall savings (*₹153.44 lakhs*) constituted 26 percent of the supplementary *appropriation* of *₹583.00 lakhs* obtained in December, 2024 and 6 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2062”	Major Head “2062”				
सतर्कता	Vigilance				
मू.	*O.*	*1830.00*			
पू.	*S.*	*583.00*	*2363.00*	*2261.12*	*-101.88*
पु.	*R.*	*-50.00*			

(I) “लोकपाल – स्थापना” के अंतर्गत *₹1830.00 लाख* के मूल प्रावधान को *₹583.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹2413.00 लाख* तक बढ़ाया गया। तथापि, *₹151.88 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) रिक्त पदों को न भरने और कम वाहन किराए पर लेने के कारण हुई।

(I) Under “Lokpal - Establishment” - the original provision of *₹1830.00 lakhs* was augmented to *₹2413.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹583.00 lakhs*. However, there was a saving of *₹151.88 lakhs* (including supplementary *appropriation*) - due to non-filling up of vacant posts and hiring of less vehicles.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹4602.89 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹24652.00 लाख के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹4602.89 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grants of ₹24652.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	13429.00	14230.00	14007.56	-222.44
पु.	R.	801.00			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	41597.00			
पू.	S.	16378.00	60909.00	60751.38	-157.62
पु.	R.	2934.00			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय सामान्य सेवाएं	Secretariat General Services				
मू.	O.	23388.00			
पू.	S.	2430.00	20973.50	20449.29	-524.21
पु.	R.	-4844.50			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	86789.00			
पू.	S.	2720.00	94490.00	94321.83	-168.17
पु.	R.	4981.00			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	38225.00			
पू.	S.	3124.00	35082.50	33947.05	-1135.45
पु.	R.	-6266.50			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹23068.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2430.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹25498.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5264.52 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तिथि तय न होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और सेंट्रल विस्टा में प्रस्तावित स्थानांतरण के कारण खरीद गतिविधियों में कमी होने के कारण हुई।

(A) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions" - the original provision of ₹23068.00 lakhs was augmented to ₹25498.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2430.00 lakhs. However, there was savings of ₹5264.52 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards salaries and allowances, non-finalization of Common Eligibility Test (CET) date, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and reduction of procurement activities owing to proposed shift to the Central Vista.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण – अन्य प्रशिक्षण योजनाएँ" के अंतर्गत ₹6010.80 लाख के मूल प्रावधान को ₹896.00 लाख के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाकर ₹6906.80 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2986.04 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विदेश में प्रशिक्षण आयोजित न किए जाने और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि (एसीटीआई) हेतु संशोधित तौर–तरीकों के साथ सभी के लिए प्रशिक्षण (टीएफढ) योजना में सुधार की वजह से व्यय को अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(B) Under Major Head "2070" - "Training - Other Training Schemes"- the original provision of ₹6010.80 lakhs was augmented to ₹6906.80 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹896.00 lakh. However, there was a saving of ₹2986.04 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conduction of foreign training by Cadre Controlling Authorities and Central Training Institutes and postponement of expenditure to next financial year owing to revamp in Training for All (TFA) scheme with revised modalities for Augmentation of Capacity of Training Institutes (ACTI).

(II) मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2070" - "Training" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी"– ₹7153.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹7853.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो विक्रेताओं द्वारा बिल जमा करने में देरी, भुगतान शर्तों का पूरा न होने की वजह से भुगतान स्थगित होने के कारण ₹203.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(A) "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - the original provision of ₹7153.00 lakhs was augmented to ₹7853.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹700.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹203.09 lakhs - due to delay in submission of bills by

vendors, deferred payment owing to nonfulfillment of payment conditions.

(खा) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम"– ₹5439.20 लाख के मूल प्रावधान को ₹1528.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6967.20 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय सुनवाई सप्ताह के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों की बातचीत के संचालन और कार्यक्रम समन्वयकों की भर्ती न होने के कारण ₹907.91 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(B) "National Programme for Civil Services & Capacity Building" - the original provision of ₹5439.20 lakhs was augmented to ₹6967.20 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1528.00 lakhs which, however, remain unutilized to the extent of ₹907.91 lakhs - due to conduction of talk of eminent personalities for National hearing week through webinar and non-recruitment of programme coordinators.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान" – ₹611.12 लाख की बचत (₹2669.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाठ्यक्रमों के रद्द/स्थगित होने, कम दौरे किए जाने और कार्यालय उपकरणों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(A) "Institute of Secretariat Training and Management" - savings of ₹611.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2669.00 lakhs) was due to cancellation/postponement of courses, less tours undertaken and less procurement of office equipments.

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "केन्द्रीय सूचना आयोग" – ₹676.81 लाख की बचत (₹3190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने की वजह से कम पेशेवरों की नियुक्ति किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की योजना" – ₹3540.30 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी, आम चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लोगू होने के कारण सीएसडी/पीएम पुरस्कारों का आयोजन न होने और वर्चुअल मोड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Central Information Commission" - saving of ₹676.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3190.00 lakhs) was due to hiring of less professionals owing to less appointment of Information Commission.

(b) "Scheme of D/o Administrative Reforms & Public Grievances" - saving of ₹3540.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to delay in tender process, non-conduction of CSD/PM Awards on account of model code of conduct for General Elections 2024 and organising of various events on virtual mode.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:—

(I) मुख्य शीर्ष "2014" — "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण — स्थापना" — ₹578.56 लाख का अधिक व्यय (₹13429.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 16 नए सदस्यों सहित रिक्त पदों को भरने, विभिन्न स्थानों पर सर्किट पीठ की बैठक आयोजित करने और चिकित्सा दावों के निपटान के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2051" — "कर्मचारी चयन आयोग — स्थापना" — ₹2797.81 लाख का अधिक व्यय (₹16378.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹57893.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परीक्षा आयोजित करने के लिए टाटा कनसल्टेंसी सर्विसिज/इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया जैसे सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "2055" — "आपराधिक जांच और सतर्कता — केंद्रीय जांच ब्यूरो" — ₹4859.41 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2024 में प्राप्त ₹2720.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹89388.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीबीआई कर्मचारियों के वेतन और वेतन वृद्धि, यात्रा भता दावों की प्रतिपूर्ति और विभिन्न सेवाओं के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) "प्रशिक्षण" —

(का) "भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान" — ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और पेंशन, आउटसोर्स कार्मिकों के लिए बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी और परिसर में चल रहे कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "एलबीएसएनएए में बुनियादी ढांचे में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन" — ₹828.00 लाख का

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) Major Head "2014" - "Central Administrative Tribunal - Establishment" - excess of ₹578.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13429.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts including 16 new members, conduction of meeting of the circuit benches at various places and settlement of Medical claims.

(II) Major Head "2051" - "Staff Selection Commission - Establishment" - excess ₹2797.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹57893.30 lakhs including supplementary grant of ₹16378.00 lakh obtained in December, 2024) was due to payment to service providers such as Tata Consultancy Service/Electronics Corporation of India Limited for conducting the examinations.

(III) Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - excess ₹4859.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹89388.40 lakhs including supplementary grant of ₹2720.00 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of additional funds towards salary and increment of CBI staff, reimbursement of Travelling Allowance claims and settlement of pending bills of various services.

(IV) "Training" -

(A) "Grant to Indian Institute of Public Administration" - excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and pensions, enhanced minimum wages for outsourced workers and ongoing work in campus.

(B) "Improvement of infrastructure and upgradation of essential facilities at LBSNAA" -

अधिक व्यय (₹3107.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के संबंध में कार्यालय स्थान के लिए एनडीएमसी को किराए के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

excess of ₹828.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3107.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent to NDMC for office space in respect of National Centre for Good Governance (NCGG).

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹871.92 लाख* की कुल बचतें हुई और ये दिसंबर, 2024 में प्राप्त *₹2850.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 31 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत *विनियोग* का 19 प्रतिशत हैं।

4. In the *charged* portion of capital section of the grant, the overall savings *₹871.92 lakhs* constituted 31 percent of the supplementary *appropriation* of *₹2850.00 lakhs* obtained in December, 2024 and 19 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	*O.*	*1002.00*			
पू.	*S.*	*2850.00*	*3222.00*	*3210.49*	*-11.51*
पु.	*R.*	*-630.00*			

(I) "कार्यालय भवन – निर्माण – लोकपाल के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण" के अंतर्गत *₹1002.00 लाख* के मूल प्रावधान को *₹2850.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹3852.00 लाख* कर दिया गया। तथापि, *₹641.51 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) भारत के लोकपाल कार्यालय को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर में स्थानांतरित करने में देरी होने के कारण हुई।

(I) Under "Office building - Construction - Acquisition of Land & Construction of Building for Lokpal" - the original provision of *₹1002.00 lakhs* was augmented to *₹3852.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹2850.00 lakh.* However, there was a saving of *₹641.51 lakhs* (including supplementary *appropriation*) was due to delay in shifting of the office of Lokpal of India to World Trade Centre, Nauroji Nagar.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"					
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police					
मू.	O.	5512.00		4205.99	4127.59	-78.40
पु.	R.	-1306.01				
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"					
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	14836.00				
पू.	S.	1.00		13436.01	13475.22	39.21
पु.	R.	-1400.99				
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"					
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services					
मू.	O.	5009.00		3538.50	3431.87	-106.63
पु.	R.	-1470.50				

(I) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किया गया ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Token supplementary provision of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024 remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "अन्य व्यय – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹1384.41 लाख की बचत (₹5512.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनबीसीसी को मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में संशोधित निर्मित क्षेत्र से संबंधित भुगतान करने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Central Bureau of Investigation" - saving of ₹1384.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5512.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for making payment to NBCC related to the modified built up area at Maidangarhi, New Delhi.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – आईएसटीएम" के अंतर्गत ₹4485.52 लाख की बचत (₹5701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भवन का निर्माण पूरा न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "General - Construction - ISTM"- saving of ₹4485.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5701.00 lakhs) was due to non-completion of construction of new building.

(IV) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹1577.13 लाख की बचत (₹5009.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीबीआई शाखाओं द्वारा कंप्यूटर, हार्डवेयर और अन्य उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Secretariat General Services" - saving of ₹1577.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5009.00 lakhs) was due to less procurement of computers, hardware and other equipment by CBI branches.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹643.16 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 39 प्रतिशत थी।

(V) Under two heads savings of ₹643.16 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 16 percent and 39 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें (₹3797.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए का आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3767.90 लाख था।

6. The above savings were partly (₹3797.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "4059" - "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration". Actual excess, however, was ₹3767.90 lakhs.